

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 56/2014

बउनवान

सरकार जयें तहसीलदार, मांगरोल जिला-बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. केदारलाल पुत्र दानमल
2. प्रेमबाई पुत्री दानमल जातिगण मीना निवासीगण महुआ तहसील मांगरोल

(अप्रार्थीगण)



रेफरेंस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :-1. परोकार सरकार

(प्रार्थी)

2. श्री जयेश सक्सेना, अभिभाषक

(अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक- 25.04.2022

1- प्रार्थी सरकार जयें तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख०न० 54/1084 रकबा 0.32 है. किस्म नहरी । वाके ग्राम रायथल तहसील-मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067-70 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2014-2023 में खसरा नम्बर मि. 26 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई रहे है, वर्तमान सेटलमेंट संवत् 2044-63 में भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर 54/1084 रकबा 0.32 हैं कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.तलाई की किस्म नहरी । दर्ज कर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दिया। केचमेन्ट वर्ष 2008-09 में उक्त आराजी के नवीन खसरा नंबर 1283 रकबा 0.31 है. कायम किये गये हैं। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा-16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरुद्ध है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/ नियमनो को विधि विरुद्ध मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 के तहत अवैधानिक है तथा डी०बी० सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004



अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2- प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ज सम्मन तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण को जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी बन्द किया गया।

3- हमने बहस उभयपक्ष सुनी। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम रायथल की आराजी साबिक खसरा नम्बर मि. 26 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई को भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट कार्य अप्रार्थीगण के अवैधानिक रूप से खाते दर्ज कर दिया। जिस वक्त खाते दर्ज की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0न0 54/1084 रकबा 0.32 है। बने है तथा केचमेन्ट वर्ष 2008-09 में 0.01 है। की सामान्य कटौती की जाकर खसरा नंबर 1283 रकबा 0.31 है। कायम हुये हैं, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म नहरी 1 दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरुद्ध हुआ है। ऐसे नियम विरुद्ध आवंटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियाँ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत उक्त आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा-82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4- बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 1283 रकबा 0.31 है। वाके ग्राम रायथल की किस्म नहरी 1 है जो तलाई के स्वरूप में स्थित नहीं है। विवादित आराजी वर्तमान में खाल नाल तलाई की श्रेणी में नहीं है ओर वर्तमान स्थिति में बिल्कुल समतल जमीन है जहां पर पानी का ठहराव नहीं है। विवादित आराजी वर्तमान में कृषि योग्य भूमि है। उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो से बाहर जाकर की है अप्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार है उक्त आराजी के अतिरिक्त अप्रार्थीगण के पास अन्य कोई आराजी जीवन यापन के लिये नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, मांगरोल द्वारा 35-40 वर्ष से अधिक समय पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है



M
जिला कलक्टर
बांस (राज.)

जबकि उक्त आवंटन/नियमन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाही प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।

5- हमने परोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014-23 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर मि. 26 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थीगण के पिता को आवंटन/नियमन किया गया है।

6- उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट संवत् 2044-63 नये खसरा नम्बर 54/1084 रकबा 0.32 है0 बने है तथा केचमेन्ट वर्ष 2008-09 में खसरा नंबर 1283 रकबा 0.31 है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन/नियमन अप्रार्थीगण के पिता को विधि विरुद्ध हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरुद्ध मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7- परिणास्वरूप, प्रार्थी जयें तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेंस प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम रायथल में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1283 रकबा 0.31 है0 किस्म नहरी 1, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर मि. 26 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका अप्रार्थीगण के पिता को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-82 के अन्तर्गत रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8- तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंस होने का नोट लाल स्याही से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 13.04.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारा
बारा (राज.)